



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

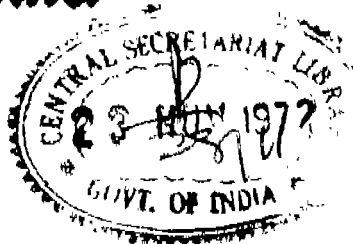
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



नं० 446] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 9, 1972/आश्विन 17, 1894

No 446] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 9, 1972/ASVINA 17, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 9th October 1972

S.O. 649(E)/18A/IDRA/72.—Whereas the Central Government is of the opinion that Luxminarayan Cotton Mills Limited, Rishra (District Hooghly), an industrial undertaking in respect of which an investigation has been made under section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is being managed in a manner highly detrimental to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 18A of the said Act, the Central Government hereby authorises the following body of persons:—

Chairman

1. Shri A. Bose, Special Officer and ex-officio Secretary to the Government of West Bengal, Department of Closed and Sick Industries, Calcutta—
2. Shri D. K. Banerjee, W.B.C.S. (Executive)—Member and Chief Executive Officer.

Member

3. Shri M. M. Sanyal, Commercial Accountant, Directorate of Labour, West Bengal—Member.

(1771)

(hereinafter referred to as the authorised body of persons) to take over the management of the whole of the said undertaking, namely, Luxminarayan Cotton Mills Limited Rishra, subject to the following terms and conditions, namely:—

- (i) the authorised body of persons shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;
 - (ii) the authorised body of persons shall hold office for five years from the date of publication of this order in the Official Gazette;
 - (iii) the Central Government may terminate the appointment of the authorised body of persons earlier, if it considers it necessary to do so.
2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. F. 3/38/72-CUC.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1972

का०आ० 649(अ)/18ए/आई डी आर ए/72.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि लक्ष्मी-नारायण काटन मिल्स लिमिटेड, रिश्रा (जिला हुगली), औद्योगिक उपक्रम का, जिसकी बाबत उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के अधीन अन्वेषण किया जा चुका है, प्रबन्ध इस रीति से किया जा रहा है कि लोकहित में अति अहितकर है :

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 18क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित व्यक्तियों,

अध्यक्ष

1. श्री ए० बोस,
विशेष अधिकारी और पदेन सचिव
पश्चिम बंगाल सरकार,
बंद और अव्यवस्थित उद्योग विभाग,
कलकत्ता—
2. श्री डी० के० बनर्जी,
डब्ल्यू बी सी एस (कार्यकारी)—सदस्य
और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।

सदस्य

3. श्री एम० एम० संयाल,
वाणिज्यिक लेखापाल,
श्रम निदेशालय,
पश्चिम बंगाल—

के निकाय को (जिसे इसमें उसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्तियों का निकाय कहा गया है) उक्त उपक्रम अर्थात् लक्ष्मीनारायण काटन मिल्स लिमिटेड, रिश्वा का पूर्ण प्रबन्ध निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए ग्रहण करने के लिये एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

- (1) प्राधिकृत व्यक्तियों का निकाय केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निकाले गये सभी निदेशों का पालन करेगा ;
 - (2) प्राधिकृत व्यक्तियों का निकाय राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष के लिये पदासीन रहेगा ;
 - (3) केन्द्रीय सरकार, प्राधिकृत व्यक्तियों के निकाय की नियुक्ति यदि, वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो, पहले ही समाप्त कर सकेगी ।
2. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी होगा ।

[सं० फा० 3/38/72-सी०यू०सी०]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव ।

